सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-28 अंक-14 22 जुलाई से 5 अगस्त, 2013 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

विश्व सर्वहारा के महान नेता फ्रेडरिक एंगेल्स लाल सलाम

''पूंजीपति वर्ग अपने खुद के लाभ के लिए हर मुमकिन तरीके से सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है!... एक पार्टी के तौर पर राज्य की ताकत के तौर पर, ... कानून केवल इस वजह से जरूरी है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास कुछ नहीं है; हालांकि यह सीधे-सीधे कुछ ही कानूनों में अभिव्यक्त है जैसे उदाहरण के लिए खानाबदोशों और फक्कड़ों के खिलाफ कानून जिनमें एक मायने में सर्वहारा ही विधिबहिष्कृत हैं, फिर भी सर्वहारा के प्रति दुश्मनी इतने जोरदार ढंग से कानून का आधार है कि जज और खासकर जस्टिसिज ऑफ द पीस जो खुद बुर्जुआ हैं और जिनके साथ सर्वहारा का ज्यादातर सम्पर्क होता है, बिना किसी और लिहाज के कानूनों में यह मतलब साफ देखता है। अगर एक अमीर आदमी अदालत के सामने हाजिर होने के लिए लाया जाए या पेशी पर बुलाया जाए तो जज अफसोस जाहिर करता है कि उसे इतनी बड़ी जहमत देनी पड़ी, यथासम्भव मामले को अनुकूल ढंग से निपटायेंगे और अगर उसे आरोपी को सजा देने के लिए मजबूर होना पड़े तो ऐसा वह बहुत ही अफसोस के साथ करता है वगैरह, वगैरह; और इस सबके अन्त में होता है एक मामूली जुर्माना, जिसे अवहेलना के साथ बुर्जुआ टेबल पर फेंकता है और चला जाता है। लेकिन अगर एक गरीब 'शैतान' ऐसी स्थिति में पड़ जाता है जिसमें उसे जस्टिसिज ऑफ पीस के सामने पेश होना पड़ता है–तो वह लगभग हमेशा ही अपने जैसे लोगों की भीड़ के साथ थाने में रात गुजारता है–उसे शुरूआत से ही दोषी मान लिया जाता है; ''ओह! हम बहाना से वाकिफ हैं'' इस तिरस्कारपूर्ण उक्ति के साथ उसके बचाव को दरकिनार कर दिया जाता है और इतना जुर्माना लगाया जाता है जिसे वह अदा नहीं कर सकता और कई महीने उसे जेल में चक्की पीसनी पड़ती है। अगर उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होता है तब भी उसे चक्की पीसनी पड़ती है'' एक आवारा और खानाबदोश होने की वजह से... और पुलिस का व्यवहार भी जस्टिसिज ऑफ पीस के ही समरूप होता है। बुर्जुआ जो चाहे कर सकता है और पुलिस सदा विनम्र बनी रहती है, कानून का सख्ती से पालन करती है, लेकिन सर्वहारा के साथ बदतमीजी और बेरहमी से पेश आती है; उसकी गरीबी दो काम करती उस पर हर तरह के अपराध का संदेह पैदा करती है और कानून के रखवालों की किसी भी सनक के खिलाफ कानूनी राहत से उसे काट देती है। इसलिए कानून का सुरक्षात्मक स्वरूप उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं रखता है, बिना किसी औपचारिकता के पुलिस बल उसके घर में घुस जाता है, उसे गिरफ्तार करता है और गाली-गलौज करता है... इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मजदूर-आदमी के लिए कानून का सुरक्षात्मक पक्ष कितना कम मौजूद है, कैसे अक्सर उसे कानून का सारा बोझ वहन करना पड़ता है इसके लाभों का फायदा उठाये बिना।''

-फ्रेडरिक एंगेल्स (इंग्लैण्ड में मजदूर वर्ग की दशा)

सर्वहारा के महान नेता, इस युग के श्रेष्ठ मार्क्सवादी चिन्तनकार
कॉमरेड शिवदास घोष लाल सलाम

सर्वहारा के महान् नेता, इस युग के अग्रणी मार्क्सवादी चिन्तनकार व क्रान्तिकारी पार्टी एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष की 5 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। देश के मेहनतकशों के लिए यह दिन उनके जीवन-संघर्षों को तहेदिल से याद करने का दिन है। हम उनके विचारों व शिक्षाओं पर चलते हुए पूंजीवाद-विरोधी जनआन्दोलन को आगे बढ़ाने और खुद को असली कम्युनिस्ट बनाने का संकल्प लेते हैं। मानव समाज में कोई भी महान आदर्श चरित्र के माध्यम से मूर्त रूप लेता है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद इस युग का श्रेष्ठतम दर्शन है। यह विज्ञान पर आधारित एकमात्र दर्शन है जिसे इस्तेमाल कर इन्सान सच्चाई व यथार्थ को जान सकता है और न केवल खुद को बल्कि अपने देश, दुनिया और समाज को भी बदल सकता है। साम्राज्यवादी-पूंजीवादी शोषण-शासन का खात्मा कर समाज को प्रगति पथ पर आगे ले जाने के लिए शोषित-पीड़ित मेहनतकश वर्ग के हाथों में यह एक अजेय हथियार है। स्थान-काल को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

उत्तराखण्ड के आपदा प्रभावित 250 गांव – कस्बों में मेडिकल सर्विस सेण्टर ने पहुंचाई चिकित्सा राहत सेवाएं

अब तक 37 कैम्पों में किया 6000 लोगों का इलाज

16 जुलाई को मावलंकर सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुखातिब एमएसएसी के डा. अंशुमान मित्रा

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली पहुंचने पर 16 जुलाई को मावलंकर सभागार में मेडिकल सर्विस सेण्टर की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें मेडिकल सर्विस सेण्टर के डा. अंशुमान मित्रा ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक दर्दनाक प्राकृतिक आपदा की त्रासदी हुई है। वहां अभी तक सरकारी हिसाब से 10 हजार से ज्यादा लोग मारे गये हैं। हमें खबर मिली है कि मृतकों की असली संख्या इससे दुगुनी से भी ज्यादा है। 5 हजार से ज्यादा लोग सरकारी तौर पर अभी तक भी लापता बताये जा रहे हैं। इस इलाके में पहाड़ी नदी-नालों के किनारे-किनारे जो लोग बसते है, उनके हजार से ज्यादा गांवों का सफाया हो गया है। भारी संख्या में लोग पत्थरों और मलबे के नीचे दब गये हैं या नदियों की तेज जलधारा में बह गये हैं, बहुत सारे घायल हुए हैं, अनेक पंगु होकर जैसे-तैसे अभी भी जिन्दा हैं। ऐसे में मेडिकल सर्विस सेण्टर ने बड़ी प्रशंसनीय पहलकदमी की है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बिहार में छात्रों की मौत पर एसयूसीआई (सी) ने किया रोष प्रदर्शन

पटना । बिहार के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से मासूम बच्चों की हुई दर्दनाक मौत की घटना पर 17 जुलाई को एसयूसीआई (सी) कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। कॉमरेड साधना मिश्रा ने इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराने, दोषियों को कड़ी सजा देने और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की माँग की।

एसयूसीआई(सी) नेताओं ने कहा कि मिड डे मील से लगभग 25 मासूम बच्चों की मौत और 60 अन्य की हालत गंभीर होने की त्रासदी ने 'सुशासन' का दावा करने वाली सरकार की घोर लापरवाही को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कॉ. शिवदास घोष...

(पृष्ठ 3 का शेष)

देखते हुए इस वैज्ञानिक विचारधारा के सही इस्तेमाल से सामाजिक क्रान्ति लायी जा सकती है। इस देश की सरजमीन पर कॉमरेड शिवदास घोष ही वह हस्ती हैं जिन्होंने जीवन के तमाम पहलुओं को समेट कर चौतरफा संघर्ष के जरिये मार्क्सवाद-लेनिनवाद को उन्नत, विकसित और समृद्ध किया है और इसी के आधार पर कॉमरेड शिवदास घोष में इस क्रान्तिकारी आदर्श ने मूर्त रूप लिया है। पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति और शिवदास घोष का नाम आज एकाकार हो गया है। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन में आये भटकावों व संशोधनवाद-सुधारवाद के खिलाफ कॉमरेड शिवदास घोष जीवनपर्यन्त दृढ़ता से लड़ते रहे। आज उनकी शिक्षाएं विश्व स्तर पर कम्युनिस्टों को प्रेरित करती हैं तथा उनका मार्गदर्शन करती हैं।

कॉमरेड घोष ने दिखाया था कि आजादी आन्दोलन में एक सही कम्युनिस्ट पार्टी होती तो आजादी आन्दोलन की गैरसमझौतावादी क्रान्तिकारी धारा के साथ एका कायम कर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन चला सकती थी और समाजवाद कायम किया जा सकता था। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नाम से जो पार्टी उस वक्त थी जो आज सीपीआई, सीपीएम व कई नक्सली धड़ों में बंटी हुई है, वह कभी भी चरित्र, आचरण व व्यवहार से एक सही कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रही। इसने स्वतन्त्रता संग्राम की गैरसमझौतावादी क्रान्तिकारी धारा का समर्थन नहीं किया। देश के ठोस हालात के बारे में इनका जायजा व रणनीति हमेशा गलत रही है। देश के पूंजीपति वर्ग को ये अपना दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त मानती रही हैं। सही कम्युनिस्ट पार्टी न होने से शहीदों की इतनी कुर्बानियों से हासिल आजादी का सारा फल पूंजीपतियों ने हड़प लिया। कांग्रेस आम आदमी की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की पार्टी थी और है। कॉमरेड घोष इस नतीजे पर पहुंचे कि हर तरह के शोषण से छुटकारा पाने के लिये देश में एक सही क्रान्तिकारी पार्टी का होना पहली शर्त है। लिहाजा आजादी आन्दोलन के अपने चन्द साथियों को लेकर उन्होंने 24 अप्रैल 1948 को एक सही क्रान्तिकारी पार्टी एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) की स्थापना की और देशभर में इसे फैलाने व बनाने के क्रम में शोषित-पीड़ित जनता की लड़ाई लड़ने में आजीवन लगे रहे। आज 22-23 राज्यों में यह पार्टी मेहनतकश जनता को जगा रही है, उसे संगठित कर जनजीवन के ज्वलंत मुद्दों पर जनआन्दोलन कर रही है।

हमारे देश की आजादी के 65 साल बाद भी पूंजीवादी शोषण की चक्की में पिस कर आम आदमी का जीवन बेहद संकट में घिर गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी व बदहाली बढ़ती जा रही है। शिक्षा, इलाज, बिजली-पानी, रोडवेज मुनाफा लूटने की चीजें बना दी गई हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। सिर्फ चंद अमीरों के लिए विकास हुआ है। सरकारी खजाने से पूंजीपतियों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। बड़े भारी घोटाले हो रहे हैं। इनमें संलिप्त हैं बड़ी-बड़ी शासक पार्टियों के नेता-मंत्री और भ्रष्ट अफसर। इसने पूंजीवादी सभ्यता के चेहरे से नकाब हटा दिया है। मनरेगा में भी भारी भ्रष्टाचार है। मजदूरों व गरीबों के अपनी यूनियन बनाने व संगठित होने के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। आये दिन डिजल-पैट्रोल के दाम बढ़ाये जा रहे हैं और कृषि भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं दिये जाते। वे कर्ज में फंसकर आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहे हैं। खुदरा में एफ.डी.आई. को लाने से हालात और भी खराब होंगे। अश्लीलता, शराबखोरी, जुआ, सट्टा को बढ़ावा देकर लोगों, खासकर नौजवानों की नैतिक रीढ़ को तोड़ा जा रहा है ताकि अन्याय-अत्याचार के खिलाफ कोई सर न उठा सके। महिलाओं पर अत्याचार और नारीत्व का अपमान असहनीय-अवर्णनीय है। चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, बच्चियों के अपहरण व महिलाओं की तस्करी आदि अपराध दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें रोकने में पुलिस-प्रशासन पंगु नजर आता है। लेकिन अन्याय का प्रतिवाद करने या अपने हक की आवाज उठाने पर उसे दबाने, जनआन्दोलनों को कुचलने में यही पुलिस-प्रशासन पूरी तत्परता दिखाता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, सी.पी.एम.-सी.पी.आई. की या किसी अन्य दल की हो, पूंजीपतियों की ताबेदार इनकी सरकारों का चरित्र जनविरोधी रहा है। सरकार बदलती हैं लेकिन मंहगाई-बेरोजगारी बढ़ाने वाली निजीकरण-भूमण्डलीकरण की जनविरोधी नीतियां वही रहती हैं। इनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है। मेहनतकश लोगों के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। वोट बैंक की राजनीति की माहिर पार्टियां व उनके नेता जात-पात, इलाका, धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर लोगों में फूट डाल रहे हैं। हाल ही में उत्तराखण्ड की भीषण तबाही को भी वे वोट बैंक से जोड़ने से बाज नहीं आये। चरित्र-इन्सानियत-सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मटियामेट किया जा रहा है। चुनाव ही जिनके लिए सब कुछ हैं उन पार्टियों को चुनाव जीतने के लिये धन बल व प्रचार बल के साथ-साथ बाहु बल भी चाहिए। इसीलिये वे अपराधियों को शह, संरक्षण व बढ़ावा दे रही हैं। समाज में नरक जैसे इन सब हालात के लिये कोई और नहीं, बल्कि 1947 से देश में कायम शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था व इसकी ताबेदार पार्टियां जिम्मेवार हैं।

दिवंगत महान् नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने बहुत पहले सन् 1948 में ही दिखाया था कि पूंजीवादी व्यवस्था, अधिकतम मुनाफा लूटना ही जिसका नियम है, अपना प्रगतिशील चरित्र खो चुकी है। यह गहरी आर्थिक मन्दी में फंस कर समाज के विकास में बाधा बन चुकी है। यह न्याय, बराबरी, आजादी, नागरिक अधिकार, मानवता, नारी-मुक्ति व जनतन्त्र का निरन्तर गला घोंट रही है। कॉमरेड शिवदास घोष चिन्तनधारा इस सच्चाई को साफ तौर पर दिखा रही है कि जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक मेहनतकशों को असली मुक्ति नहीं मिल पायेगी। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बरकरार रहने से समाज में और भी ज्यादा सड़न-गलन प्रकट होती जाएगी। दिनों दिन इसका नंगा व घृणित रूप सामने आ भी रहा है। केवल जनआन्दोलन और उसकी सफल परिणति के तौर पर क्रान्ति के जरिये ही वास्तविक जन-मुक्ति हासिल हो पायेगी।

कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि इस सर्वहारा क्रान्ति का सेनानी होना ही सही मायने में ईज्जत से जीने का रास्ता है। हमारे सामने जबरदस्त संभावनाएं खुल रही हैं। कॉमरेड घोष की शिक्षाओं और जीवन-संघर्ष के पहलुओं को जानना व समझना है। यह दिन अपने महान नेता के प्रति शोक और दुख-दर्द को फर्ज की दृढ़ता में तब्दील कर क्रान्तिकारी बनने के कठिन संघर्ष में और भी तनदेही से जुट जाने का आह्वान करता है।

बिहार में छात्रों की मौत. ..

(पृष्ठ 1 का शेष)

उजागर कर दिया है। सरकार मिड डे मील के लिए जो धन आवंटित करती है वह नाकाफी है। फिर मिड डे मील में भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी और घटिया खाद्यान्न उपलब्ध कराना आम बात हो गई है। उन्होंने इस मुजरिमाना लापरवाही को नाकाबिले बर्दाश्त बताया। इस दूर करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावर्ती न हो। बच्चों के हाथों में कटोरा थमा कर शिक्षा कतई भी उन्नत नहीं की जा सकती। मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिलों में भी एसयूसीआई(सी) द्वारा प्रदर्शन किये गये।

बिहार के युवाओं का राजनैतिक शिक्षण शिविर

घाटशिला (झारखण्ड) में स्थित मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिन्तनधारा अध्ययन केन्द्र में 15से 17 जून तक ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ), बिहार राज्य कमेटी के तत्वावधान में तीन दिवसीय राजनैतिक शिक्षण शिविर आयोजित हुआ। शिविर की शुरूआत केन्द्र में स्थापित कॉमरेड शिवदास घोष की प्रतिमा पर माल्यार्पण, झण्डात्तोलन और कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गान से हुई।

शिविर का संचालन एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड अरूण कुमार सिंह ने किया। पहले से निर्धारित 'मार्क्सवाद व मानव समाज के विकास के बारे में' पुस्तक में वर्णित विकास के तीन सूत्रों पर विशद् चर्चा हुई। इस चर्चा से उभरे सवालों पर प्रतिनिधियों के बीच फिर सामूहिक चर्चा हुई और प्रतिनिधियों से आमन्त्रित सवालों पर भी चर्चा हुई। दूसरे दिन शाम के सत्र में प्रतिनिधियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, काव्यपाठ आदि प्रस्तुत किये गये।

तीसरे दिन समापन सत्र में 'युवा जीवन की समस्याएं और मौजूदा आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संकट की परिस्थितियों में युवाओं का दायित्व' पर चर्चा हुई। कॉमरेड सिंह द्वारा की गई इस सारगर्भित व जीवन्त चर्चा से युवाओं के मन-मस्तिष्क स्पन्दित हो गये। संक्षेप में उनकी चर्चा का सार यह था कि शोषण और मुनाफे पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था के बरकरार रहते युवा जीवन व मानव जीवन की बुनियादी समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। इसलिए उच्च नीति-नैतिकता, मूल्यबोध और चरित्र हासिल करते हुए युवाओं को संगठित कर पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति के परिपूरक युवा आन्दोलन तेज करना युवाओं का मुख्य दायित्व बनता है।

समापन सत्र से पहले ऑल इण्डिया डी.वाई.ओ. के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड दीपक कुमार ने देश के विभिन्न प्रान्तों में चल रहे युवा आन्दोलन के विस्तार, प्रभाव व महत्व के बारे में बताया जिससे वहां मौजूद नौजवान बड़े उत्साहित हुए। उन्होंने बिहार में भी नौजवानों को संगठित कर युवा आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया। अन्तर्राष्ट्रीय गान के साथ इस शिक्षण शिविर का समापन हुआ।

इस तीन दिन के कैम्प जीवन से अनुशासित व सामूहिक रहन-सहन की सीख व संकल्प लेकर फौलादी इरादे के साथ प्रतिनिधि युवा वापस लौटे।

कॉ. प्रतिभा मुखर्जी श्रद्धांजली सभा

रांची (झारखण्ड)। रांची में 13 जुलाई को एआईएमएसएस और एआईडीएसओ की जिला कमेटियों के संयुक्त तत्वावधान में कॉमरेड प्रतिभा मुखर्जी की स्मरण सभा पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। सभा में सर्वप्रथम कॉमरेड प्रतिभा मुखर्जी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली दी। तत्पश्चात् एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के झारखण्ड राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति ने कॉमरेड प्रतिभा मुखर्जी के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कॉमरेड प्रतिभा मुखर्जी ने अपने छात्र जीवन से लेकर अन्तिम सांस तक सिर्फ पार्टी और क्रान्ति के लिए ही काम किया। वे पार्टी के निर्देशानुसार हर क्षेत्र में जन आन्दोलन गठित करने और उसे मजबूत करने में प्रयासरत रही। हमें भी उनके जीवन-संघर्ष से प्रेरणा और सीख लेकर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण-जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए।

सभा में कॉमरेड सिद्धेश्वर, केया डे, स्वरूप मण्डल, विवेक, शिखा, कल्पना, सूरजमनी व अन्य कई साथी उपस्थित थे।

कॉमरेड शंकर साहा ने की अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में शिरकत

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आई एल सी) का 102वां सत्र जनेवा में 5 से 20 जून, 2013 तक आयोजित किया गया। ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन सेन्टर (एआईयूटीयूसी) के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने इण्डियन वर्कर्स डेलिगेशन के सदस्य के रूप में सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने 20 जून को हुए प्लेनरी सत्र में मजदूरों के विभिन्न अधिकारों पर बात रखी और हड़ताल का मौलिक अधिकार छीनने के लिए बार-बार की जा रही सुनियोजित कोशिश पर बोले जिसका मूल पाठ नीचे दिया जा रहा है। 185 देशों के प्रतिनिधियों की सभा ने उनके भाषण की सराहना की।

20 जून को प्लेनरी सत्र में कॉमरेड शंकर साहा द्वारा दिया गया भाषण

प्रिय चेयरमेन और प्रतिनिधिगण,

विश्व भर में बुनियादी मानव अधिकार यानी हड़ताल के अधिकार को छीन लेने की सुनियोजित और संगठित कोशिश के संदर्भ में मैं भारतीय श्रमिक, शंकर साहा बोल रहा हूँ। प्रिय चेयरमेन, मैं भूमण्डलीकरण का हवाला दे रहा हूँ क्योंकि यह एक वास्तविकता है और भूमण्डलीय मजदूरों के अधिकारों और जीवन के हालातों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मजदूर समुदाय को पंगु बना देने के लिए व्यवस्था खुद उनको निहत्था कर देना चाहती है ताकि व्यवस्था के खिलाफ कोई प्रभावशाली प्रतिवाद न हो सके जिसने मजदूरों के बेरहम शोषण के जरिये मुनाफे को अधिकतम करते जाने के इस युग में पूंजीवाद के जीवन की घड़ियों को लम्बा करने के लिए भूमण्डलीकरण को लागू किया है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस पूंजीवादी भूमण्डलीकरण के तहत पूरी विश्व अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व मंदी के संकट में डूब गई है जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका को ढह जाने के कगार पर ला दिया है। पूंजीवाद का इंजन कहलाने वाला अमेरिका आज सबसे बड़ा कर्जवान राष्ट्र बन गया है और अपनी सारी साख गवां चुका है। फिलहाल, इसकी बेरोजगारी दर 10% को पार कर गई है, अर्धबेरोजगारी लगभग 17% है, हर 6 अमेरिकियों में से एक अमेरिकी गरीबी रेखा से नीचे है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों इत्यादि में भारी कटौती ने औसत अमरिकियों का जीना दूभर कर दिया है। लीडर नेशन का ऐसा ही मॉडल इसके अनुयायी–ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि अख्तियार कर रहे हैं। यूरोप के तमाम दिग्गज या तो दिवालिया हो गये हैं या दिवालिया हो जाने के कगार पर हैं। यूरोप का तथाकथित रक्षक, जर्मनी भी संकटग्रस्त है। यूरोपियन यूनियन ने पुष्टि की है कि यूरो जोन 2013 में सिंकुड़ जाएगा। ऐशियाई दिग्गज भी हिले हुए हैं। हम अन्य विकासशील देशों की बात नहीं कर रहे हैं जहां पहले ही लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देशों की सरकारें मितव्ययता के कदम उठा रही हैं और इसी क्रम में लोगों को उनके संघर्षों से अर्जित अधिकारों से वंचित करके, वेतन और पेन्शन में कटौती करके, रोजगार हानियों, रोजगारों की असुरक्षा, आकार कटौती, ले-ऑफों, उच्च बेरोजगारी, मूलभूत नागरिक सेवाओं से पीछे हटने के जरिये मेहनतकश लोगों पर वीभत्स हमले जारी रखे हुए है। इसके विपरीत कार्पोरेट और एकाधिकारी पूंजीपतियों को प्रोत्साहन पैकेज, इन्सेन्टिव, रियायतें और टैक्सों में छूट आदि दे रही हैं यानी जो शोषक हैं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए जो लोग शोषित हैं उन्हें ठगा जा रहा है। यह आम आदमी पर वित्तीय पूंजी के खुले शोषण का आयोजन है। जहां पूरी धन-सम्पदा चंद मुट्ठी भर हाथों में संचित है, वहीं 80% से ज्यादा आबादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित है।

साथियो, भूमण्डलीकरण न केवल आर्थिक तौर पर शोषण करता है, बल्कि पूरे समाज को सांस्कृतिक तौर पर, नीति-नैतिक तौर पर पतित करने के जरिये धूर्तता के साथ मानव सभ्यता को तबाह कर रहा है, फूहड़पन, चरम उपभोक्तावाद, घोर आत्मकेन्द्रिकता और सामाजिक फर्ज के प्रति उदासीनता को बढ़ावा दे रहा है।

हड़ताल की तो बात छोड़ दीजिए, मेहनतकश लोगों, शोषित-पीड़ित लोगों द्वारा की जाने वाली प्रतिवाद की किसी कार्रवाई के खिलाफ है यह व्यवस्था। यह मजदूरों की एकता, सुदृढ़ीकरण और संघर्ष से डरती है। यूरोप, अमेरिका, मध्य-पूर्व, एशियाई देशों में जारी आन्दोलन और महत्वपूर्ण रूप से अमेरिकी जनता का जुझारू आन्दोलन–'वाल स्ट्रीट दखल करो आन्दोलन', जिसमें नारा उठा ,'हम 99% हैं और तुम 1%'। इसमें शासक पूंजीपतियों को अपनी मौत की घण्टी बजती सुनाई देती है।

प्रिय साथियो, आइये स्थिति को समझें। मजदूर काम का अधिकार चाहते हैं लेकिन दिया नहीं जा रहा है। वे संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार चाहते हैं लेकिन नकार दिया जाता है। वे स्वास्थ्य सेवा, आवास और वृद्धावस्था हितलाभ चाहते हैं लेकिन इनसे वंचित हैं। उन्हें सामूहिक तौर पर तयशुदा मेहनताना और अन्य हितलाभ नहीं दिये जाते हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। फायदा उठाने के लिए बच्चों और महिलाओं की तस्करी आज का चलन हो गया है। दुनिया भर में प्रवासी मजदूरों को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं और बंधुआ मजदूरों की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। खैर चाहे जो भी हो, यह व्यवस्था जो हर घड़ी अपनी मौत का इन्तजार कर रही है हड़ताल सहित किसी भी आन्दोलन का सामना नहीं कर सकती।

मजदूरों को सिखाया जाता है कि जैसी जनवाद और स्वतंत्रता मालिकों को प्राप्त है वैसी उन्हें भी है। लेकिन अमानवीय हमलों और यातनाओं से रूबरू होने पर सामाजिक हितरक्षा करने और जनवादी व मानवीय मूल्यों को बुलन्द रखने की खातिर हड़ताल की जरूरत को मजदूर समझते हैं, सरकार जो शोषणमूलक व्यवस्था की रक्षा करती है हड़ताल करते ही मजदूरों पर टूट पड़ेगी। इस प्रकार बुर्जुआ जनवाद के मिथक का पर्दाफाश हो जाता है। असल में शोषकों के लिए शोषण करने की पूरी आजादी और और डैमोक्रेसी है, अन्य किसी को नहीं। हड़ताल के अधिकार के बिना मजदूरों के लिए डैमोक्रेसी का कोई कोई मायने नहीं है। अगर हड़ताल का अधिकार छीन लिया गया तो राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में दिये गये सैकड़ों अधिकार भी बेमानी हो जायेंगे। यह स्थिति हमें गुलामाना दौर की याद दिलाती है जब काम बंद करना उस समाज में अपराध था।

प्रिय दोस्तो, इसीलिए सभ्यता, मजदूरों की अन्तर्राष्ट्रीय बरादरी से और उनके मयार्दा और इज्जत बोध से स्थिति की गम्भीरता का अहसास करने की मांग करती है और आजादी, डैमोक्रेसी और हड़ताल का अधिकार जो मौजूदा समाज में मजदूरों का बुनियादी मानवाधिकार है, सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने की मांग करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

"मौजूदा आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक संकट और प्रगतिशील ताकतों की भूमिका" विषयक परिचर्चा आयोजित

पटना(बिहार) । एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी के तत्वावधान में 7 जुलाई को यहां आई. एम. ए. हाल में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय था: मौजूदा आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक संकट और प्रगतिशील ताकतों की भूमिका।

मुख्य वक्ता थे साप्ताहिक बांग्ला पत्रिका 'गणदाबी' के सम्पादक मंडल सदस्य तथा एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी सदस्य कॉ. अमिताभ चटर्जी। देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया परिवर्तन के लिए पुकार रही है। आज पूरी आर्थिक व्यवस्था घनघोर मंदी की चपेट में है। पूंजीवादी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि मानवीय मूल्य, नैतिकता, इंसानियत अभूतपूर्व संकटों की शिकार है। मुट्ठीभर लोग अमीर बन रहे हैं जबकि बहुसंख्यक अवाम का जीवन तबाह हो रहा है। आजादी के बाद से अब तक विकास के नाम पर जनता के साथ छलावा किया जाता रहा है। लाखों किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर किया गया है। अनगिनत कारखाने बंद पड़े हैं। लाखों मजदूर-कर्मचारी छंटनी के शिकार हुए हैं। आम जनता महंगाई की असहनीय पीड़ा से कराह रही है। मौजूदा राजनैतिक संकट पर चर्चा के क्रम में कॉ. चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद आदि तमाम संसदीय पार्टियां पूंजीपतियों की हितरक्षक हैं। एक समय था कि जब छात्र-नौजवान राजनैतिक नेताओं को अपना मॉडल समझते थे, उनके जैसा बनने का सपना पालते थे, लेकिन आज कोई भी उनके चरित्र को अपनाने की बात नहीं सोचता। करीब-करीब सभी संसदीय व वोट आधारित पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। वे विभिन्न तरह के घपलों-घोटालों में शामिल पाये जाते हैं। बिहार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुशासन और सामाजिक न्याय के नाम पर नीतीश सरकार भी केन्द्र में कांग्रेस नेतृत्ववाली यूपीए तथा राज्य में पूर्व की राजद सरकार की तरह ही निजीकरण, व्यवसायीकरण व पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप की जनविरोधी नीतियों को लेकर चल रही है। महिलाओं पर जुल्म तथा अपराध की घटनाओं में इजाफा जारी है। सरकार सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, जन परिवहन, नगर निगम आदि विभागों में निजीकरण को बढ़ावा ही नहीं दे रही है, बल्कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर जनता के विभिन्न तबकों द्वारा उभर रहे जन आंदोलनों का भी दमन कर रही है। हत्या, बलात्कार, अपहरण और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकतम मुनाफा कमाने के उद्देश्य से संचालित पूंजीवादी व्यवस्था ही इन तमाम समस्याओं की जननी है। समाज के प्रति छात्र-युवाओं में उदासीनता, सामाजिक और मानवीय मूल्यों में गिरावट, सामाजिक जिम्मेवारी बोध में कमी और सबसे बढ़कर बड़ों के प्रति असम्मान की बढ़ती मानसिकता–ये सभी प्रवृत्तियां मौजूदा शोषणमूलक व्यवस्था से ही पैदा हो रही हैं। पूंजीवाद को उखाड़ फेंककर शोषणहीन समाज बनाने के वास्ते चल रहे संघर्ष में शामिल होने के लिए उन्होंने उपस्थित प्रबुद्ध जनों से अपील की।

पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रो. देवेन्द्र प्रसाद ने परिचर्चा की अध्यक्षता की। प्रख्यात अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी, बाल गोविन्द सिंह, आर. एन. झा तथा एसयूसीआई (सी) पटना जिला कमिटी सचिव साधना मिश्रा ने परिचर्चा में भाग लिया। एसयूसीआई (सी) बिहार राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अरूण कुमार सिंह मंच पर उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड में आपदा राहत कार्य...

(पृष्ठ 1 का शेष)

मेडिकल सर्विस सेण्टर के नाम से आप भलीभांति वाकिफ हैं। एमएससी के संयुक्त सचिव डॉ. अंशुमान मित्रा और वी.एस.दहिया ने बताया कि मेडिकल सर्विस सेन्टर (एम.एस.सी.) एक राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी संगठन है जिसका लक्ष्य है संकट, अभाव व विशेषकर आपदा के समय सभी को निशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान करना। यह संगठन चिकित्सा के हर क्षेत्र में कार्यरत जनोन्मुखी मानसिकता वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों व देश भर में फैले अपने सदस्यों की स्वैच्छिक सेवाओं तथा आम जनता एवं समान विचारधारा वाले संगठनों द्वारा दिए गए अनुदान से चलता है। आज 18 राज्यों व 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में एम.एस.सी. काम कर रहा है। देश की करोड़ों करोड़ जनता की दुर्दशा के दु:ख-दर्द को महसूस करते हुए उनके स्तर को ऊपर उठाने की भावना व प्रतिबद्धता इसे दूसरे संगठनों से अलग करती है। चिकित्सा सेवा से और ऊपर उठ कर जन-स्वास्थ्य से जुड़े वर्तमान मुद्दों व प्रचलित तथा उभरते हुए नीतिगत मामलों के प्रति जनता को संवेदनशील बनाने के आंदोलन में एम.एस.सी. नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर रहा है। चिकित्सा क्षेत्र के अग्रदूतों के जीवन संघर्ष को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए तथा नैतिकता के क्षरण, सड़ी हुई व्यक्तिवादी सोच व स्वास्थ्य व शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुकाबला करने के लिए एम.एस.सी. एक प्रकाश स्तम्भ की तरह है। पिछले साढ़े तीन दशकों से आम जनता में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने, गरीब बस्तियों में मेडिकल कैम्प लगाने, कालोनियों, उपनगरों व नगरों में विशेष मेडिकल कैम्प लगाने, मेडिकल कॉलेजों व अन्य चिकित्सीय संस्थानों में चिकित्सकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में उच्च स्तर की नैतिकता पनपाने तथा जनविरोधी स्वास्थ्य नीतियों के विरोध में आंदोलन संचालित करने के साथ साथ विशेषकर प्राकृतिक आपदा के समय में चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। लातूर के भूकम्प, ओड़िसा के सुपर साइक्लोन, गुजरात के भूकम्प और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में एम.एस.सी. की आपदा राहत टीम ने अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तराखंड में हुई तबाही के आकलन व वहां आपदा राहत भेजने के अग्रिम इंतजाम के लिए 23 जून 2013 को सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इंडिया (कम्यूनिस्ट) ने सर्वप्रथम अपनी एक 4 सदस्यीय टीम प्रभावित क्षेत्र में भेजी जिसने साथ-साथ वहां स्थानीय लोगों की मदद भी जुटाई। वहां के स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से सहर्ष सहयोग दिया। एम.एस.सी. के संयुक्त सचिव व डिजास्टर रिस्पॉन्स सैल के इंचार्ज डा. अंशुमान मित्र के नेतृत्व में 28 जून को रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में विकास भवन में पहला मेडिकल बेस कैम्प स्थापित किया। एस.यू.सी.आई (सी) के कार्यकर्ताओं की मदद से इसी बेस कैम्प से मोबाइल मेडिकल टीमें प्रभावित गांवों में जा जाकर लोगों का इलाज कर रही हैं। इस दायरे में ऐसे गांव भी शामिल किए गये हैं जो सड़कों के टूटने से बाकी क्षेत्र से अलग-थलग हो गए हैं और जहां यातायात के कोई साधन नहीं हैं। स्वयंसेवक सिरों पर राहत सामग्री, दवाइयों के डिब्बे आदि लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं। खतरों से खेलते हुए, बड़े दुर्गम रास्तों से होकर और खराब मौसम सहित तमाम प्रतिकूलताओं से जूझते हुए पीड़ितों के इलाज का मेडिकल सर्विस सेण्टर ने बड़ा सराहनीय काम किया है।

नासिक मेडिकल कॉलेज के आर्थोपीडिक्स विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनायक नार्लेकर और एम.एस.सी. के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 2 जुलाई 2013 को एक एडवांस बेस कैम्प बांसवाड़ा तथा भीड़ी में लगाया गया। इसी क्रम में बांसवाड़ा में एक क्लीनिकल प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। देश के विभिन्न राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यू.पी. व चंडीगढ़ से आये एमएससी के 100 से अधिक स्वयंसेवी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनमें डाक्टर, विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मी सम्मिलित हैं। अभी तक अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और यह क्रम अभी जारी है। अभी तक कुल 37 कैम्प आयोजित किये जा चुके हैं जिनमें 250 से अधिक गांवों एवं कस्बों को कवर किया गया है। इन कैम्पों में अब तक लगभग 6000 रोगियों को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस कार्य में लगभग 7.5 लाख रुपये की दवाइयां तथा 6 लाख रुपये से ज्यादा राशि अन्य कार्यों में खर्च हुई है जिसे देश के विभिन्न राज्यों में आम जनता से अनुदान के रूप में एकत्र किया गया था।

समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पिछले तीन सप्ताह में किये गये कार्यों एवं अनुभवों के आधार पर उन्होंने निम्नलिखित तथ्य व सुझाव प्रस्तुत किये(जो रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला विकास अधिकारी से भी साझा किये जा चुके हैं) –1. प्रभावित क्षेत्रों में जलजनित रोग, पेट का संक्रमण, पीलिया, कीट संक्रमण आदि बीमारियां अधिक मात्र में पाई गई जो दूषित एवं अपर्याप्त पेयजल तथा कलोरीनेशन की कमी से फैल रही हैं। एमएससी का प्रयास है कि एक अन्य संगठन 'ब्रेक थ्रू साइन्स सोसायटी' जो एक सामाजिक वैज्ञानिक संगठन है, की मदद से जागरूकता अभियान चला कर पेयजल हेतु फिल्टर के निर्माण एवं प्रयोग की

(शेष पृष्ठ 5 पर)

पटना में आईएमए हाल में परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए एमएससी के डा. अशोक सामंत। परिचर्चा में एसयूसीआई (सी) के सांसद डा. तरुण मण्डल भी उपस्थित थे

मेडिकल कैम्प में अनुशासित ढंग से इलाज कराते हुए ग्रामीण

कर्णप्रयाग में मेडिकल कैम्प में रोगियों का इलाज करते हुए प्रो. नर्लीकर

मेडिकल कैम्प में सहयोग देते ग्रामीण युवा

चन्द्रापुरी : तबाही हुई उससे कुछ ही दूरी पर मेडिकल कैम्प

उत्तराखण्ड में आपदा राहत

(पृष्ठ 4 का शेष)

मेडिकल कैम्प में रोगियों को देखते स्वास्थ्य कर्मी

जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। 2. श्वसन व त्वचा संक्रमण (चर्म रोग) भी स्थानीय लोगों में अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। 3. मानसिक विचलन, गम्भीर मानसिक दबाव (स्ट्रेस) उन परिवार के सदस्यों में अधिक देखने को मिला जहां लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है, रोजगार के साधन नष्ट हो गए हैं, परिवार जन मौत के मुंह में चले गए हैं या उनका कोई प्रियजन लापता है। सुझाव है कि स्थानीय परिवारों से लापता लोगों को खोजने में प्रशासन को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिये जितना तीर्थयात्रियों को दिया जा रहा है। 4. प्रभावित परिवारों की गुजर-बसर व रोजगार शुरू करने हेतु तात्कालिक राहत के तौर कुछ धन का अनुदान तुरंत दिया जाए और हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाए। 5. स्वयं सेवी स्वास्थ्य राहत टीम जो सड़क से वंचित दूरदराज के गांवों में अपनी सेवायें देना चाहती हों, उन्हें आवश्यक संसाधन दिए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिये। चूंकि उत्तराखण्ड के प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य राहत शिविरों की लम्बे समय तक आवश्यकता अभी बनी रहेगी अत: मेडिकल सर्विस सेंटर मीडिया के माध्यम से यह अपील करता है कि ऐसे आयोजन के लिये चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी वालंटीयर के रूप में आगे आएं व अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए प्रभावित इलाकों में स्वैच्छिक कार्य करने हेतु अपने आप को प्रस्तुत करें। आम जनता से भी हम हर तरह के सहयोग व अनुदान की अपेक्षा करते हैं।

मुख्य स्थान जहां स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये गए, वे हैं रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग, चन्द्रापुरी, सिल्ली, चोपड़ा, सुमाड़ी, तिलवाड़ा, बांसवाड़ा, अगत्सयमुनी, जवाड़ी, दरमोला, दरमाड़ी, ककोला, रामपुर-चाकापलाठी, सुरसल, जलोई, बड़ाडुंगरा, तूना-बूफा चमोली जिले में कर्णप्रयाग आदि स्थान मेडिकल सर्विस सेण्टर का फिलहाल यहां कार्यक्षेत्र है। यहां रुद्रप्रयाग, चोपड़ा, अनसारी, हिटनाग, दरमोला, चन्द्रापुरी, सिमरी, रतूड़ा, बुदुली, मोहनखाल, कुमरी, सतेराखाल, रतोड़ा, सुमेरपुर, आमसारी, क्यारकी, रतोला, रेवाड़ी, रेहनतोली, तुना, श्रीनगर, मयाली, डोंगरी, गौचर, जवाड़ी, खांखरा, सोत, टकोली, घिमतोली, अगत्सयमुनी, हाटा, रूमरी, मनीगुहा, कुण्ड, उखीमठ, कमसल, भौराल, डोबा, जगोन्त, अमोठा, फलाती, सिल्ली, भटगांव, नकोट, टांगे, सौरी, तिलवाड़ा, बस्ती, परकण्डी, काण्डी, दामर, जलाई, बांसवाड़ा, भीरी, बिलोई, गौचर, कोली, जयमण्डी, मयाली, न्योलासियोथोली, तूना, तिलोई, जवारी, लोली, कर्णप्रयाग, जिलासर, दीमार, अहिरबाड़ी, कुण्ड-दुर्गा, कत्यारी, गोपेश्वर, मटियाला, सिरन, कालेष्ठवर, सालना, वल्ली, बड़मा, थापुटी, सोनाली, रतुड़ा, करचुना, जिदोली, नारायणबगड़, पडली, बासकोली, दियोतोली, सन, स्यूण्ड, सुरसाल, परकण्डी, औरिंग, नेहारा, फेगु, टिमरिया, ककोला, दरसाल, दुर्गानगर, थान्ड व पेलिंग आदि मुख्य गांवों और कस्बों में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की गई।

कहीं भी जगह मिली, वहीं बैठ कर दवाइयां देते हुए स्वयंसेवक

देश के विभिन्न प्रांतों से दवाइयां संग्रह करते हुए स्वयंसेवक

भीड़ी में चल रहा एडवान्स्ड कैम्प

जलाई गांव में रोगियों की जांच करते हुए मोबाइल टीम

ब्लड सैम्पल लेते हुए मोबाइल लैब टीम

ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन–भारत संयुक्त सेमिनार

बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 24–25 जून को रोजगार व सामाजिक नीति पर छठा यूरोपियन यूनियन–भारत संयुक्त सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार का खास मुद्दा था ''सामाजिक सुरक्षा''। भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑल इण्डिया यूनाइटिड ट्रेड यूनियन सेण्टर (एआईयूटीयूसी) के अन्यतम उपाध्यक्ष कॉमरेड सी के लुकोस ने इसमें शिरकत की। एटक, बीएमएस व सीटू के प्रतिनिधि भी भारत के मजदूर ग्रुप में थे। इस तरह भारत से नियोक्ताओं के ग्रुप से 6, सरकार पक्ष के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से 4 अधिकारी और मजदूरों की ओर से उपरोक्त 4 प्रतिनिधि थे। अन्य प्रतिनिधि यूरोपियन कमिशन, यूरोपियन वर्कर्स और सामाजिक संबंधित ग्रुपों से थे। कुल मिला कर 80 प्रतिनिधियों ने सेमिनार में शिरकत की।

यूरोपियन प्रतिनिधि पक्ष से व्यावहारिक तौर पर जिन्होंने भी बात रखी, उन सभी ने वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संकट का जिक्र किया। सेमिनार में वितरित किये गये एप्रोच पेपर में भी यह कहा गया कि ''संकट का असर और जनसंख्या का तेजी से बूढ़ी होते जाना सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उनके मौजूदा रूप में बनाये रखने को और भी मुश्किल बनाता जा रहा है। जबकि भारत से सरकारी अधिकारियों की ओर से सब कुछ मनरेगा, आईसीडीएस, शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिकार बिल वगैरह, वगैरह जैसी सामाजिक सुरक्षा के लिए ली गई स्कीमों और विभिन्न विधि–विधानों का महिमामंडन था।

बीएमएस के अखिल भारतीय सचिव श्री के पी सिंह, एटक के नेता श्री एम एल यादव और सीटू के राष्ट्रीय सचिव डा. कश्मीर सिंह ठाकुर ने भी बात रखी।

कॉमरेड सी के लुकोस

25 जून को चौथे सत्र में भाग लेते हुए कॉमरेड सी के लुकोस ने ''सामाजिक सुरक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार'' विषय पर अपना पेपर पेश किया।

सभी बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ पार्टियां देश के पूंजीपतियों के स्वार्थ में काम कर रही हैं

पत्रकार सम्मेलन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) लोकसभा सदस्य डॉ. तरुण मंडल

पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) के सांसद डॉ. तरुण मंडल (दाहिने से दूसरे)

पटना (बिहार)। यहां 13 जुलाई को आई. एम. ए. हॉल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) के सांसद डॉ. तरुण मंडल ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने की हवस में दुनिया के अमन–चैन का दुश्मन बना हुआ है। ज्ञात हो कि सांसद डा. तरुण मंडल ने ही संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषण का बहिष्कार किया था। उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि भारत का शासक वर्ग देश की साम्राज्यवाद–विरोधी परम्परा को ताक पर रखकर अमेरिका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों का जूनियर पार्टनर बनकर देश–दुनिया की मेहनतकश आम जनता को बर्बादी की ओर ले जा रहा है।

भाजपा–जदयू गठबंधन टूटने पर डॉ. तरुण मंडल ने कहा कि चाहे एनडीए हो या यूपीए –कोई भी गठबंधन देश की आम जनता का हितरक्षक नहीं है। ये गठबंधन इन वोट बटोरू पार्टियों द्वारा सत्ता में जाने और अपने आका पूंजीपति वर्ग के हित साधने के मकसद से बने हैं। इनके टूटने और बनने में आम जनता का हित कहीं नहीं है। नीतीश कुमार की इस बात को उन्होंने हास्यास्पद करार दिया कि नरेन्द्र मोदी साम्प्रदायिक हैं और भाजपा नहीं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा को छोड़कर नरेन्द्र मोदी की क्या हैसियत है। डॉक्टर तरुण मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार का जदयु, कांग्रेस, भाजपा, राजद, सपा, बसपा, टीएमसी, डीएमके आदि तमाम बुर्जुआ व पेटी बुर्जुआ पार्टियां इस देश के पूंजीपतियों के स्वार्थ में काम कर रही हैं। आम जनता को अपने हक–अधिकार के लिए संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीपीआई, सीपीआई (एम) आज जन आंदोलन के रास्ते से भटक गयी हैं। आज इनका एकमात्र मकसद है किसी तरह जोड़–तोड़ कर सत्ता में आना, एमपी–एमएलए सीटें हासिल करना। यह पूछे जाने पर कि देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं को लेकर वाम पार्टियां एकत्रित होकर संघर्ष के मैदान में क्यों नहीं उतर रही हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल सीपीआई (एम)–सीपीआई कभी सही कम्युनिस्ट थी ही नहीं। इन तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियों, खासकर सीपीआई (एम) ने पश्चिम बंगाल में लम्बे दिनों तक सत्ता में रहने के दौरान केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का ही अनुसरण किया, सिर्फ इतना ही नहीं जनआंदोलनों का बर्बरता के साथ दमन किया, जिसकी मिसाल हमें सिंगुर–नन्दीग्राम में जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए किसान आंदोलन में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि जनता को अपने न्यायसंगत सवालों को लेकर जन कमिटियों का निर्माण करते हुए दीर्घस्थायी व जुझारू जन आंदोलन का निर्माण करना होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जन आंदोलनों में उनकी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) अगली कतार में रहेगी, जैसा कि वह अपनी स्थापना काल से ही करती आयी है। एक सवाल के जवाब में पश्चिम बंगाल के जयनगर लोकसभाई क्षेत्र के सांसद ने कहा कि आतंकवाद मनुष्य द्वारा मनुष्य के बेरहम शोषण पर आधारित पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था की उपज है। जब तक पूंजीवाद–साम्राज्यवाद रहेगा, तब तक आतंकवाद रहेगा। आतंकवाद और युद्धों से छुटकारा पाने के लिए जनजीवन के ज्वलंत सवालों पर एकताबद्ध दीर्घस्थायी आंदोलन की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया।

संसद में सांसदों की वेतन वृद्धि का विरोध करने वाले एकमात्र सांसद डॉ. तरुण मंडल ने कहा कि जब देश की जनता कमरतोड़ महंगाई, भयंकर बेरोजगारी से जूझ रही है। देश के किसान लाखों की तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं। छोटे–बड़े लाखों बंद कल–कारखानों के लाखों मजदूर–कर्मचारी भूखमरी के शिकार हैं। ऐसे में जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करने की मांग करना अनैतिक है। उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ वेतन वे अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों और मरीजों के इलाज पर खर्च करते हैं। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) सांसद ने कहा कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) देश के 20 से अधिक राज्यों में केन्द्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जिस तरह सड़कों पर संघर्ष कर रही है, उसी तरह पार्टी लाइन के आधार पर वे एकमात्र सांसद होकर भी संसद में जन सवालों को उठा रहे हैं, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस मौके पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड अरूण कुमार सिंह भी मौजूद थे।

परमाणु बिजली संयंत्र लगाये जाने का विरोध

हिसार (हरियाणा)। गोरखपुर में परमाणु बिजली संयंत्र लगाये जाने के विरोध में यहां स्थानीय जाट धर्मशाला में ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन के तत्वावधान में 6 जुलाई को किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सरकार की किसान–विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। सम्मेलन में गोरखपुर में प्रस्तावित परमाणु बिजली संयंत्र लगाना बंद करने, बिजली उत्पादन के लिए वैकल्पिक साधनों को इस्तेमाल करने और इस संयंत्र के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि किसानों को वापस लौटाने की मांग की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसान खेत मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रही है।

इस अवसर पर संगठन के राज्य सचिव कॉमरेड

विजय कुमार, नंदलाल, देवीराम, हवा सिंह, जिलेसिंह, रोहताश आदि किसान नेता भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति एवो मोरालेस के जहाज को जबरन उतरने पर मजबूर करने की घृणित कार्रवाई की एआईसीसी ने की कड़ी निन्दा

अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी कॉऑर्डिनेटिंग कमेटी के महासचिव कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने 5 जुलाई को निम्न प्रैस विज्ञप्ति जारी की :

बोलिविया के राष्ट्रपति एवो मोरालेस को ले जा रहे विमान को जबरन नीचे उतरने को मजबूर करने की गुण्डागर्दी की कार्रवाई की अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी कॉऑर्डिनेटिंग कमेटी (एआईसीसी) कड़ी निन्दा करती है। विमान को इस शक पर उतरने को मजबूर किया गया कि यह अमेरिका की नजर में अपराधी, स्नोडेन को लेकर जा रहा था। मास्को छोड़ने से पहले राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने ऐलान किया था कि अगर स्नोडेन राजनैतिक शरण लेना चाहें तो इस पर बातचीत हो सकती है और विचार किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोप भाजन बनने के लिए इतना ही काफी था। राष्ट्रपति एवो मोरालेस के विमान की उड़ान को फ्रांस, इटली, पुर्तगाल व स्पेन ने एयर स्पेश देने से इनकार कर दिया और वियना में उतरने को मजबूर कर दिया गया जहां आस्ट्रियाई अधिकारियों ने स्नोडेन है कि नहीं यह देखने के लिए उसकी तलाशी लेने की मांग की और विमान को 14 घण्टे डिटेन करके रखा। साफ जाहिर है कि यह सब अमेरिका के दबाव में किया गया। स्नोडेन कोई अपराधी नहीं है, उल्टे उसने तो शक्तिशाली अमेरिकी सरकार की आपराधिक गतिविधियों का भण्डाफोड़ कर मानवजाति की महान सेवा की है। मानव अधिकार की विश्वजनीन घोषणा की धारा 14 कहती है कि ''हर किसी को अभियोजन से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेने और उपभोग करने का अधिकार है।'' जाहिर है कि यह घटना एक गुण्डागर्दी की कार्रवाई के तुल्य है और राष्ट्रपति एवो मोरालेस के साथ जो सलूक किया गया वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और मर्यादा की सब हदें पार गया है। लोकतंत्र के तथाकथित चैम्पियन, यूरोप के इन देशों की इस कानून की तौहीन करने वाली कार्रवाई की भी एआईसीसी कड़ी निन्दा करती है जिन्होंने अमेरिका के फरमान पर इसे अंजाम दिया। साम्राज्यवादी ताकतों की ये घोर गैरकानूनी कार्रवाइयां इसलिए की जा सकी कि साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ कारगर और जोरदार संयुक्त वैश्विक जन आन्दोलन नदारद है। एआईसीसी सभी प्रगतिशील ताकतों से सभी देशों में जोरदार साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन गठित करने और साम्राज्यवाद के खिलाफ वैश्विक आन्दोलन छेड़ने के लिए इन सब के बीच तालमेल करने की अपील करती है।

सामूहिक बलात्कार काण्ड के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुतला दहन

रांची (झारखण्ड)। रांची में 17 जुलाई को एआईडीएसओ रांची जिला कमेटी के बैनर तले प्रतिवाद दिवस मनाया गया। विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के साथ-साथ झारखण्ड के पाकुड़ जिले के एक स्कूल के छात्रावास से 4 छात्राओं का अपहरण कर 25 नकाबपोशों द्वारा किये सामूहिक बलात्कार काण्ड के खिलाफ एआईडीएसओ के नेतृत्व में विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक से शुरू हुआ और रांची युनिवर्सिटी पहुंच कर शहीद चौक होते हुए वापस अल्बर्ट एक्का चौक आकर विरोध सभा में तब्दील हो गया। वहां पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से भी कई नेता-कार्यकर्ता शामिल हुई। रांची सहित पूरे झारखण्ड में बढ़ रही बलात्कार की घटनायें की रोकथाम करने की मांग की गई

कार्यक्रम में एआईडीएसओ रांची जिला सचिव कॉमरेड वह्निशिखा समाजपति ने कहा कि पूरे देश भर में छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रहीं हैं। शिक्षा को खरीद-फरोख्त की चीज में तब्दील किया जा रहा है। शिक्षा को मुनाफा कमाने के क्षेत्र के रूप में निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उच्च शिक्षा ही नहीं, बल्कि प्राइमरी शिक्षा भी इतनी महंगी कर दी गई है कि शिक्षा सिर्फ पैसे वालों की जागीर बन गई है। स्कूल-कॉलेजो में शिक्षको, अन्य स्टाफ और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। 8वीं तक पास-फेल प्रणाली खत्म कर शिक्षा की नींव कमजोर की जा रही है। छात्रों को कुछ आता हो या नहीं अगली कक्षा में चढ़ा यिा जाता है। वहीं सर्वशिक्षा के नाम पर खिचड़ी स्कूल चलाये जा रहे हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता की कोई गारण्टी नहीं है। आये दिन मिड डे मील में खाना खाने से छात्रों के बीमार होने और मरने की दुखद घटनायें घट रही हैं।

पाकुड़ जिले के इसीआई स्कूल के गर्ल्स होस्टल से छात्राओं के अपहरण और उनके साथ सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना की निन्दा करते हुए छात्र नेता ने बलात्कारियों को तुरन्त गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की माँग की। उन्होंने कहा कि शराब और अश्लील सिनेमा साहित्य को सरकार द्वारा बढ़ावा दिये जाने से बलात्कार जैसी घटनायें बढ़ रही हैं। उन्होंने इन सब समस्याओं के खिलाफ राजयव्यापी जोरदार छात्र आन्दोलन गठित करने का डात्र-छात्रओं से आह्वान किया।

प्रदर्शन में विवेक, अभिषेक, राहुल, संतोष, रिंकी, लिली, सुनीता, अजय, दिलीप, सहपति, अंजली व कई अन्य छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

एआईडीएसओ का बंगलौर जिला सम्मेलन

बंगलौर। यहां 13 जुलाई को यूवीसीई एल्युमनी हाल में छात्र संगठन ऑल इण्डिया डीएसओ का 7वां बंगलौर जिला सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सभी फेकल्टियों व बंगलौर की कई शिक्षण संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों ने काफी संख्या में इस सम्मेलन में शिरकत की। महापुरुषों की उद्धरणों प्रदर्शनी भी लगाई गई। सम्मेलन की शुरूआत ऑल इण्डिया डीएसओ के राज्याध्यक्ष कॉमरेड राजशेखर द्वारा शहीद वेदी पर माल्यार्पण से हुई। संगठन के कर्नाटक राज्य सचिव डा.एन.प्रमोद ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने जिन समस्याओं से छात्र रूबरू हैं उन पर विस्तार से प्रकाश डाला और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। इसके बाद राजनैतिक सांगठनिक रिपोर्ट, मुख्य प्रस्ताव, आईपीएल पर प्रस्ताव और छात्राओं की सुरक्षा पर प्रस्ताव पेश किये गये जिन पर चर्चा-बहस में प्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सम्मेलन के समापन सत्र में एसयूसीआई(सी) राज्य कमेटी सदस्य कॉ. बी.आर.मंजूनाथ ने अपने सम्बोधन में छात्रों से अपने अध्ययन के साथ-साथ सामाजिक उत्थान के लिए काम को भी बराबर महत्व देने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को अपने जीवन में कठिन संघर्ष संचालित कर अच्छे गुण हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राय जाहिर की कि छात्र केवल तभी शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस और नेताजी की विरासत व परम्परा को आगे बढ़ा पायेंगे। उन्होंने नई कमेटी को बधाई दी और शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की समस्याओं और सांस्कृतिक क्षेत्र में व्याप्त संकट का मुकाबला करने के लिए संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। सभी प्रतिनिधियों ने समय के तकाजे के मुताबिक जीवन जीने और नये जुझारू जज्बे के साथ काम करने का संकल्प लिया।

नई कमेटी में अश्वनी के एस को अध्यक्ष, धनुष किरण, अजय कामथ को उपाध्यक्ष, रविनन्दन बी बी को सचिव, कौशिक एल, शर्मा एल, ऐश्वर्य सी एम, सिन्धू आर को सचिवमण्डल सदस्य, सितारा एम, सिन्दूर एम, राजेश भट्ट, चेतन कुमार को कमेटी सदस्य और 31 अन्य को जिला काउंसिल सदस्य चुना गया।

शिक्षा बचाओ सम्मेलन

आरोन (म.प्र.)। 8वीं कक्षा तक पास-फेल खत्म किये जाने, शिक्षा के गिरते स्तर, शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण और महिलाओं पर बढ़ते यौन अपराधों के खिलाफ एआईडीएसओ द्वारा आरोन जिला गुना में 7 जुलाई को एक शिक्षा बचाओ सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के कॉमरेड मुदित भटनागर रहे। सम्मेलन को एआईडीवाईओ के स्थानीय प्रभारी कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव ने भी सम्बोधित किया। निहार सोनी और प्रमोद नामदेव ने उपस्थित छात्र समुदाय से 26 अगस्त को भोपाल में आयोजित होने जा रहे अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। एआईडीएसओ के तेजभान साहू ने सब का आभार जताया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing :20 July, 2013

जनप्रतिनिधियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों पर

एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी का बयान

सांसदों व विधायकों की सदस्यता के सवाल पर 10 और 11 जुलाई, 2013 को दिये गये सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों और चुनावों में उम्मीदवार होने की नई अयोग्यता के बारे में आदेश दिये जाने पर सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमेटी ने 14 जुलाई को निम्न बयान जारी किया :

एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी ने 10 जुलाई, 2013 को दिये गये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अत्यंत ध्यान से नोट किया है जिसमें विधानसभाओं और संसद में आपराधिक तत्वों को प्रवेश करने से रोक (डि-बार) करके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को साफ करने के वास्ते इसने यह फैसला सुनाया है कि सजायाफ्ता सांसद और विधायक तुरन्त उसी समय से संसद और विधानसभाओं के सदस्य नहीं रहेंगे और इस तरह इसने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को उनके अधिकार से परे बना डाला है। जहां एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी आपराधिक तत्वों की खतरनाक घुसपैठ को भारतीय चुनाव प्रणाली से खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सरोकार की सराहना करती है, वहीं यह दिखाना भी अपना जरूरी फर्ज समझती है कि इन दण्डित और घोर आपराधिक तत्वों का पाला-पोसा जाना और संसद व विधानसभाओं में प्रवेश पाने के लायक बनाना बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीधा प्रायोजित होता है जो सरकारें चला रही हैं, यहां तक कि वोटरों को डरा-धमका कर बाहु बल का इस्तेमाल करके येन-केन प्रकारेण अधिकाधिक सीटें जीतने के उन्मत प्रयास में उन्हे शक्तिशाली मंत्री भी बनाया जा रहा है। केन्द्रीय कमेटी यह दिखाना भी अपना जरूरी फर्ज समझती है कि मेहनतकश जनता के न्यायोचित जनवादी आन्दोलनों को दबाने और तहस-नहस करने के लिए और इसके लिए चुनावों में भाग लेने से मेहनतकश जनता के निरखे-परखे प्रतिनिधियों को रोकने (डिबार करने) के लिए जनवादी आन्दोलन में लगे हुए सैकड़ों हजारों समर्पित जुझारू कार्यकर्ताओं को अनैतिक और शरारती तरीको का सहारा लेकर आये दिन नितांत झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और इस तरह उन्हें लम्बी अवधि की सजाएं भी दिलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ यह भी दिन के उजाले की तरह साफ है कि सभी बड़ी-बड़ी बुर्जुआ और पेटी बुर्जुआ पार्टियों द्वारा अपनायी गई तिकड़मबाज और शरारत भरी राजनीति की वजह से राजनीति का यह अपराधीकरण एक बहुत भयंकर राजनीतिक समस्या, लोकतंत्र और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक सीधा हमला बन गया है। इसलिए जब तक बुर्जुआ साजिश और दुरभिसंधि के खिलाफ जोरदार जनआन्दोलन नहीं चलाया जाएगा, तब तक महज कानूनी निर्णयों, उपायों व कार्रवाइयों से इस बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो केन्द्रीय कमेटी उठाना चाहती है वह यह है कि जो उम्मीदवार मेहनतकश जनता के जायज जनवादी आन्दोलन गठित करने में लगे हुए हैं उन्हें चुनाव प्रणाली के दायरे से ही विलुप्त कर देने की मंशा से शासक बुर्जुआ पार्टियों के कहने पर अभियोजन तंत्र के राजनीतिकरण की वजह से इन्साफ का नाश या व्यर्थता अक्सर नाजायज और गलत फैसलो की ओर ले जाती है जो कई बार ऊपर की अदालतों द्वारा खारिज कर दिये जाते हैं या उलट दिये जा रहे हैं। विधानसभाओं और संसद में असली आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोकने या इन निकायों की सदस्यता का उपभोग करने से उन्हे अयोग्य ठहराने के ताकतवर निदान की हमारी खोज में जब हकीकत यह देखने में आ रही है तब इस प्रासंगिक तथ्य की अनदेखी या दोष की लिपा पोती नहीं की जा सकती है।

इन हालात में, हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का दृढ़ मत है कि इन्साफ को सुनिश्चित करने के वास्ते ऐसे मामलों का फैसला करने के लिए समूची न्यायिक प्रक्रिया को अपनी परिपूर्णता में काम करने की इजाजत देनी चाहिए। किन्ही भी हालात में यह विफल या इसके अनिवार्य घटकों में से कोई भी तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। हमारी राय में प्रथम दृष्टया मामला कसौटी हो जाने से, अपील करने का अधिकार जो कि बुनियादी अधिकार है, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है और जहां ये अपील स्वीकृत हो जाती हैं और न्यायशास्त्र की सच्ची भावना से विचार की जाती हैं तो जब तक मामले को अन्तिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता, किसी दण्डात्मक कार्रवाई का सहारा नहीं लिया जा सकता है। इसकी बजाय हम यह महसूस करते हैं कि अपील, खासकर विधायकों और सांसदों या मंत्रियों से सम्बन्धित अपीलों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से निपटाया जाना चाहिए।

हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी चुनाव लड़ना चाहने वाले व्यक्ति को जो जेल या पुलिस हिरासत में है उसे डिबार करने के सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के एक और फैसले पर भी गौर करती है। केन्द्रीय कमेटी इस बात पर जोर देना चाहती है कि तमाम लोकतांत्रिक देशों में, संसदीय प्रणाली की शुरूआत से ही यह सुस्थापित परम्परा (कन्वेन्शन) रही है कि हर अण्डर ट्रायल कैदी को चुनाव लड़ने का बेरोकटोक अधिकार है इस बात का लिहाज किये बिना कि वह जेल में है या बेल पर है क्योंकि न्यायशास्त्र का बुनियादी सिद्धान्त कहता है कि जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे बेकसूर माना जाए। फिर एक पल भर के लिए भी इस बात को भूला नहीं जा सकता कि जब बुर्जुआ राजनीति पतित हो रसातल में जा चुकी है, तब जो लोग जन आन्दोलन गठित करने में लगे हुए हैं उन्हें शासक पार्टियों द्वारा नापाक तरीकों का सहारा लेकर चुनाव से डिबार करने का प्रयास एक वास्तविक खतरा बन गया है। इसलिए हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का यह दृढ़ मत है कि ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल प्रयोजनीय नहीं है, वांछनीय भी नहीं है, मनमाने ढंग का है और व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता और आजादी पर और लोकतंत्र पर भी जंबरदस्त चोट है। इसलिए हम जोरशोर से महसूस करते है कि सुप्रीम कोर्ट शांत और ठण्डे दिमाग से इस पर विचार करे और इस आदेश को तुरन्त मन्सुख करें।

जी-8 की शिखर बैठक के विरोध में आयरलैण्ड में साम्राज्यवाद-विरोधी सभा

बेलफास्ट में साम्राज्यवाद-विरोधी मंच की बैठक में कॉमरेड माणिक मुखर्जी

दुनिया के चोटी के साम्राजयवादी देशों के शासकों के गुट जी-8 की शिखर बैठक हाल ही में आयरलैण्ड में हुई। इस बैठक के समय ही आयरलैण्ड के बेलफास्ट में साम्राज्यवाद-विरोधी मंच की बैठक बुलाई गई। 14-15 जून को आयोजित इस बैठक में शामिल हुए अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी कॉऑर्डिनेटिंग कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव कॉमरेड माणिक मुखर्जी। इस साम्राज्यवाद-विरोधी बैठक की पहल पर रिपब्लिकन सिन फिन पार्टी ने राजनैतिक बन्दियों की रिहाई को लेकर रोष प्रदर्शन किया।

14 जून के शाम के सत्र में कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने कहा कि विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गहरे आर्थिक संकट में फंस गई है और जबरदस्त मंदी ने इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। इसलिए दुनिया के बाजार के बंटवारे को लेकर साम्राज्यवादी ताकतों के बीच जबरदस्त द्वन्द्व दिखाई दे रहा है। सभी देशों में पूंजीपति वर्ग इस आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए एक तरफ तो मजदूर वर्ग पर हमले तेज कर रहा है, वहीं साथ ही साथ दूसरी तरफ गैट, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं बना कर आर्थिक व्यवस्था को अपने-अपने स्वार्थ के अनुरूप इन्हे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हर साम्राज्यवादी देश में बाजार में बनावटी तेजी लाने के लिए अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण किया जा रहा है। इस भारी अस्त्र भण्डार को खाली करने के लिए छोटे-बड़े युद्ध और झगड़े करवाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आज फिर साम्राज्यवाद-विरोधी, युद्ध-विरोधी जुझारू शान्ति आन्दोलन गठित करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

उत्तरी आयरलैण्ड में इस जी-8 बैठक को केन्द्र करके सामरिक आयोजन काफी कुछ साम्राज्यवादी दखलअन्दाजियों की तरह ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयरिश जनता की लम्बे अर्से से साम्राज्यवाद-विरोधी शानदार परम्परा रही है और वह लड़ाई अभी भी जारी है। इस पहलू से बेलफास्ट की वह बैठक काफी तात्पर्यपूर्ण है। यह बैठक एक ऐसे समय हो रही है जब सीरिया को केन्द्र करके मध्य-पूर्व में साम्राज्यवादी हमले की सम्भावना बढ़ती जा रही है। विश्वव्यापी साम्राज्यवादी हमले और कब्जे के खिलाफ हमें देश-देश में लड़ाई तेज करने की शपथ लेनी होगी और इन लड़ाइयों को संयुक्त कर साम्राज्यवाद के खिलाफ एकताबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन छेड़ने का एक दीर्घस्थायी कदम उठाना होगा। रिपब्लिकन सिन फिन पार्टी सहित आयरलैण्ड के अन्य साम्राज्यवाद-विरोधी संगठनों के साथ तुर्की, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, फिलीपीन्स, अमेरिका सरीखे देशों के संगठन इसमें शामिल हुए।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष:011-25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com; sarvaharadrishtikon@yahoo.com